

दोहरे मानक और विस्थापन की कहानी

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष एक गहरे जड़ें जमाए हुए संघर्ष है, जो ऐतिहासिक विसंगतियों और समकालीन अन्यायों से चिह्नित है, जो हिंसा और विस्थापन के चक्र को बनाए रखता है। यह निबंध चार प्रमुख विषयों की जांच करता है: नाज़ी उत्पीड़न से भागे यहूदी प्रवासियों को शरण देने में फिलिस्तीन की ऐतिहासिक भूमिका, जो बाद में स्वयं विस्थापित हो गए; ज़ायोनी अर्धसैनिक बलों और बाद में इज़राइल द्वारा आतंकवाद का उपयोग, जबकि दूसरों को आतंकवादी करार देना; मानवाधिकार मानदंड जो इज़राइल के निर्माण को संभव बनाते थे, लेकिन अब फिलिस्तीनियों के खिलाफ उल्लंघन किए जा रहे हैं; और 1947 के संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना की अनुचितता, जिसके बाद इज़राइल का अवैध विस्तार हुआ। ये विषय दोहरे मानकों, नैतिक विरोधाभासों और कानूनी उल्लंघनों का एक पैटर्न उजागर करते हैं जो फिलिस्तीनी अधिकारों को कमज़ोर करते हैं और निष्पक्ष समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

शरणस्थल के रूप में फिलिस्तीन, अब विस्थापित

1930 और 1940 के दशक में, नाज़ी जर्मनी ने यहूदियों को निष्कासित किया, न्यूरेमबर्ग कानूनों (1935) के तहत उनकी नागरिकता छीन ली, और 1938 के एंश्लूस के बाद उत्पीड़न को बढ़ाया। जुलाई 1938 में फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट द्वारा शुरू की गई इवियन सम्मेलन शरण प्रदान करने में विफल रहा: 32 देशों ने भाग लिया, लेकिन केवल डोमिनिकन गणराज्य और कोस्टा रिका ने महत्वपूर्ण संख्या (क्रमशः 100,000 और 200 परिवार) स्वीकार करने की पेशकश की, जबकि संयुक्त राज्य और ब्रिटेन ने कोटा बढ़ाने से इनकार कर दिया। सीमित विकल्पों के साथ, कई यहूदी ब्रिटिश मैंडेट फिलिस्तीन की ओर रुख किए, जहां ब्रिटिश मैंडेट ने 1917 के बालफोर घोषणा के तहत प्रवास को सुगम बनाया। 1933 से 1939 तक, 120,000 से अधिक यहूदी आए, और 1947 तक यहूदी आबादी 33% (1.9 मिलियन में से 600,000) तक पहुंच गई। इस संदर्भ में, फिलिस्तीन ने यहूदी शरणार्थियों को स्वीकार किया और बचाया जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों ने उन्हें ठुकरा दिया।

आज, इस इतिहास को ज़ायोनी कथन द्वारा उलट दिया गया है कि “कोई भी देश फिलिस्तीनियों को स्वीकार नहीं करना चाहता।” 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और गाजा में इज़राइल की जवाबी कार्रवाई के बाद से, संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, 1.9 मिलियन फिलिस्तीनी (2.1 मिलियन में से) विस्थापित हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) इन कार्रवाइयों को जिनेवा सम्मेलनों के तहत युद्ध अपराध, जबरन स्थानांतरण के रूप में दस्तावेजित करता है, जिसमें निकासी आदेश, सुरक्षित क्षेत्रों पर हमले, और गाजा के 70% आवास का विनाश शामिल है। इज़राइली अधिकारी, जैसे वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच, ने गाजा वासियों के लिए “स्वैच्छिक प्रवास” का सुझाव दिया है, जिसका अर्थ है कि उनका विस्थापन संघर्ष को हल कर देगा। यह कथन जॉर्डन, चिली, और जर्मनी जैसे देशों में 6 मिलियन फिलिस्तीनी प्रवासी समुदाय को नजरअंदाज करता है, और इस तथ्य को कि इज़राइल की नाकेबंदी और गाजा की सीमाओं (उदाहरण के लिए, रफाह क्रॉसिंग) पर नियंत्रण फिलिस्तीनियों को बाहर निकलने से रोकता है, न कि अंतरराष्ट्रीय इच्छा की कमी। विडंबना स्पष्ट है: इज़राइल, जो आंशिक रूप से उन शरणार्थियों द्वारा बनाया गया था जिन्होंने फिलिस्तीन में शरण पाई थी, अब फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित करता है जबकि यह दावा करता है कि कोई और उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय कानून (विश्व मानवाधिकार घोषणा, अनुच्छेद 13) के तहत उनकी मातृभूमि में रहने के अधिकार का उल्लंघन करता है।

आतंकवाद की निरंतरता

ज़ायोनी अर्धसैनिक बलों इर्गुन और लेही ने ब्रिटिश मैंडेट के दौरान ऐसी रणनीतियों का उपयोग किया जो आज आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश को निष्कासित करना और एक यहूदी राज्य को सुरक्षित करना था। मैनकेम बेगिन के नेतृत्व में इर्गुन ने 1946 में किंग डेविड होटल पर बमबारी की, जिसमें 91 लोग मारे गए (41 अरब, 28 ब्रिटिश, 17 यहूदी)। 1948 में देर यासीन नरसंहार, जो इर्गुन और लेही द्वारा किया गया, ने 100 से अधिक फिलिस्तीनी ग्रामीणों को मार डाला, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और नकबा तीव्र हुआ। अन्य कृत्यों में 1947 में ब्रिटिश सर्जेंट्स क्लिफर्ड मार्टिन और मर्विन पाइस की फांसी, अरब बाजारों में बम विस्फोट, और 1946 में रोम में ब्रिटिश दूतावास पर बमबारी जैसे अंतरराष्ट्रीय हमले शामिल थे। लेही ने 1944 में लॉर्ड मॉयने और 1948 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ फोल्के

बर्नार्डोट की हत्या की, जिसमें बाद वाला संभवतः इज़राइली राज्य की भागीदारी के साथ था। ये कृत्य—नागरिकों को निशाना बनाना, भय फैलाना, और राजनीतिक लक्ष्यों का पीछा करना—आधुनिक आतंकवाद की परिभाषाओं (संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 49/60, 1994) के अनुरूप हैं। बेगिन, जिन पर MI5 ने £10,000 का इनाम रखा था, बाद में इज़राइल के प्रधानमंत्री (1977-1983) बने और लिकुड पार्टी की स्थापना की, जिसका नेतृत्व आज बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं।

तब से, इज़राइल ने ऐसी कार्रवाइयां की हैं जो इस हिंसा को दर्शाती हैं, जिन्हें अक्सर आत्मरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आतंकवाद या अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में आलोचना की जाती है। 2006 में, इज़राइल ने बेरूत-रफीक हरीरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बमबारी की, नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और हजारों को फंसा दिया, जिसकी HRW ने सैन्य आवश्यकता की कमी के कारण निंदा की। 1973 में, इज़राइल ने लिबियन अरब एयरलाइंस की उड़ान 114 को मार गिराया, जिसमें 113 में से 108 लोग मारे गए, एक ऐसा कृत्य जिसे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने अवैध माना। इज़राइल ने 2001-2002 में गाजा के यासर अराफात अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी नष्ट कर दिया, जो 2007 की नाकेबंदी के तहत फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंधों का प्रतीक है। फिर भी, इज़राइल हमास के नेताओं को आतंकवादी कहता है, उन्हें हत्या के लिए निशाना बनाता है—उदाहरण के लिए, तेहरान में इस्माइल हनिया (जुलाई 2024) और रफाह में याह्या सिनवार (अक्टूबर 2024)—जबकि अपनी स्वयं की इतिहास को नजरअंदाज करता है। हमास, जिसे अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी समूह नामित किया है, ने इज़राइली नागरिकों पर हमला किया, लेकिन गाजा में 2007 की नाकेबंदी के तहत फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंधों का प्रतीक है। फिर भी, इज़राइल हमास के नेताओं को आतंकवादी कहता है, उन्हें हत्या के लिए निशाना बनाता है—उदाहरण के लिए, तेहरान में इस्माइल हनिया (जुलाई 2024) और रफाह में याह्या सिनवार (अक्टूबर 2024)—जबकि अपनी स्वयं की इतिहास को नजरअंदाज करता है। हमास, जिसे अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी समूह नामित किया है, ने इज़राइली नागरिकों पर हमला किया, लेकिन गाजा में इसकी राजनीतिक भूमिका और बयानबाजी में बदलाव (उदाहरण के लिए, 2017 का चार्टर) को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे इसे वह वैधता नहीं मिलती जो बेगिन को प्राप्त हुई थी। यह दोहरा मानक—ज़ायोनी और इज़राइली हिंसा को माफ करना जबकि फिलिस्तीनी प्रतिरोध की निंदा करना—संघर्ष के चक्र को बनाए रखता है।

मानवाधिकार: इज़राइल को सक्षम करना, फिलिस्तीनियों का उल्लंघन

मानवाधिकार मानदंड जो मैंडेट के दौरान ब्रिटिश को प्रतिबंधित करते थे, ने इज़राइल के निर्माण को संभव बनाया, लेकिन वही मानदंड अब इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ उल्लंघन किए जा रहे हैं। ब्रिटिश मैंडेट ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन के सभी निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा, जो प्रारंभिक मानवाधिकार सिद्धांतों को दर्शाता था। इर्गुन और लेही के विद्रोह का सामना करते हुए, ब्रिटिश प्रतिक्रिया संयमित थी: ऑपरेशन शार्क (1946) में गिरफ्तारियां और कफर्य शामिल थे, और पकड़े गए उग्रवादियों को इरिट्रिया, केन्या, और साइप्रस के शिविरों में निर्वासित किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश से बचा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की थकावट, अंतरराष्ट्रीय दबाव (विशेष रूप से होलोकॉस्ट के बाद अमेरिका से), और उभरते मानवाधिकार मानदंडों ने असमान्य बल प्रयोग को सीमित किया। गाजा में इज़राइल की तरह अधिक कूर प्रतिक्रिया ने ज़ायोनी आंदोलन को कुचल दिया होता, जिससे 1948 में इज़राइल की स्थापना रुक जाती।

आज, इज़राइल फिलिस्तीनियों के साथ अपने व्यवहार में इन मानदंडों का उल्लंघन करता है। अक्टूबर 2023 से, इज़राइल की गाजा में अभियान ने 1.9 मिलियन लोगों को विस्थापित किया, 43,000 से अधिक को मार डाला, और 70% आवास को नष्ट कर दिया, ऐसी कार्रवाइयां जिन्हें HRW जबरन स्थानांतरण, एक युद्ध अपराध, के रूप में वर्गीकृत करता है। 2007 की नाकेबंदी सामूहिक दंड का गठन करती है, जो चौथे जिनेवा सम्मेलन के अनुच्छेद 33 के तहत निषिद्ध है, और आवश्यक वस्त 4056ओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है। तीसरे देशों में लक्षित हत्याएं, जैसे ईरान में हनिया की हत्या, संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत गैर-न्यायिक हत्याओं के बारे में चिंताएं पैदा करती हैं। विंडब्ल्यु गहरी है: 1940 के दशक में यहूदी आबादी की रक्षा करने वाले मानदंड अब नजरअंदाज किए जाते हैं, क्योंकि इज़राइल के कार्य फिलिस्तीनियों के जीवन, आवाजाही, और स्व-निर्णय के अधिकारों को कमज़ोर करते हैं।

अनुचित विभाजन, अवैध विस्तार

1947 का संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना (संकल्प 181) स्वाभाविक रूप से अनुचित था, जिसने मैंडेट फिलिस्तीन का 56% (14,100 वर्ग किमी) एक यहूदी राज्य के लिए आवंटित किया, जो अल्पसंख्यक आबादी (33%, 600,000 लोग) के लिए था, जिसके पास केवल 7% भूमि थी, जबकि अरब बहुमत (67%, 1.3 मिलियन) को 43% (11,500 वर्ग किमी) मिला। यरुशलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर होना था। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को राज्य की ओर एक कदम के रूप में स्वीकार किया, जबकि अरब नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह स्व-निर्णय का उल्लंघन करता है। इसके बाद की 1947-1948 की गृहयुद्ध और 1948 की अरब-इज़राइल युद्ध ने इज़राइल को फिलिस्तीन के 78% (20,770 वर्ग किमी) तक विस्तारित करने के लिए प्रेरित किया, जिसने 750,000 फिलिस्तीनियों को विस्थापित किया (नकबा), देर यासीन जैसे नरसंहारों ने इस पलायन को बढ़ावा दिया।

यह 56% इज़राइल के लिए पर्याप्त नहीं था, जो तब से कब्जे, बस्तियों, और अधिग्रहण के माध्यम से अवैध रूप से विस्तारित हुआ है। 1967 की छह-दिवसीय युद्ध ने इज़राइल को वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरुशलम, और गोलन हाइट्स पर कब्जा करने में सक्षम बनाया। 2024 के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के परामर्शी राय ने इस कब्जे को अवैध घोषित किया, जिसमें वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में 700,000 से अधिक बस्तियों के माध्यम से फिलिस्तीनी स्व-निर्णय के उल्लंघनों का हवाला दिया गया, जो चौथे जिनेवा सम्मेलन के अनुच्छेद 49 के तहत अवैध हैं। फिलिस्तीनी नियमित रूप से निष्कासन का सामना करते हैं, जैसे शेख जर्राह में, बस्तियों के लिए जगह बनाने के लिए। इज़राइल का 1980 में पूर्वी यरुशलम को अपनी “अविभाजित राजधानी” के रूप में अधिग्रहण अवैध है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प A/RES/ES-10/24 (2024) ने पुनः पुष्टि की, जो बस्तियों और अलगाव दीवार की भी निंदा करता है। ये कार्य इज़राइल के नियंत्रण को मजबूत करते हैं, “अनुक्रमणीय प्रभाव” पैदा करते हैं जो अधिग्रहण के समान हैं, फिलिस्तीनियों को और अधिक विस्थापित करते हैं और विभाजन योजना में निष्पक्षता के सिद्धांतों का खंडन करते हैं।

निष्कर्ष

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष ऐतिहासिक विसंगतियों और समकालीन अन्यायों से चिह्नित है जो गहरे दोहरे मानकों को उजागर करते हैं। फिलिस्तीन ने यहूदी प्रवासियों को शरण दी जब दुनिया ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, लेकिन अब इज़राइल फिलिस्तीनियों को विस्थापित करता है जबकि यह दावा करता है कि कोई उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, उनकी दुर्दशा में अपनी भूमिका को नजरअंदाज करते हुए। ज़ायोनी अर्धसैनिक बलों ने एक राज्य बनाने के लिए आतंकवाद का उपयोग किया, और इज़राइल ने बाद में समान कार्य किए—हवाई अड्डों पर बमबारी, हवाई जहाजों को मार गिराना—जबकि हमास को आतंकवादी करार देता है, बेगिन के आतंकवादी अतीत के बावजूद। मानवाधिकार मानदंड जो इज़राइल के निर्माण को संभव बनाते थे, अब फिलिस्तीनियों के खिलाफ उल्लंघन किए जा रहे हैं, जैसा कि गाजा में जबरन स्थानांतरण और नाकेबंदी से स्पष्ट है। 1947 का अनुचित विभाजन, इसके बाद बस्तियों और अधिग्रहण के माध्यम से इज़राइल का अवैध विस्तार, इस विस्थापन के पैटर्न को जारी रखता है, अंतरराष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये विरोधाभास जवाबदेही और एक ऐसे समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं जो फिलिस्तीनी स्व-निर्णय का सम्मान करता हो, इस संघर्ष के केंद्र में ऐतिहासिक शिकायतों और समकालीन अन्यायों को संबोधित करता हो।